मैन्यूफैक्चरिंग को मिलेगी सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा

सरकार ने नीति तैयार करने के लिए बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को दिए निर्देश

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

- ताप बिजली से बने उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाने की काट है यह कदम
- अधिकारियों ने कहा-इस परियोजना को लागू करने के लिए करने होंगे कई बदलाव

दुनिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कुछ देशों की तरफ से उन सभी उत्पादों के आयात को हतोत्साहित करने की कोशिश शुरू हो गई है जिनके उत्पादन में कोयला से बनी बिजली का इस्तेमाल किया गया हो। यूरोपीय संघ ने तो इस बारे में नए नियमों को लागू भी कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे आने वाले दिनों में भारत में निर्मित स्टील के आयात में बाधा पैदा हो सकती है।

सरकार ने इस आशंका को भांपते हुए इस बात की संभावना तलाशना शुरू कर दिया है कि क्या देश के समूचे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से ही बिजली दी जाए। इस बारे में देश के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बिजली और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वैसे उक्त दोनों मंत्रालयों के अधिकारी मान रहे हैं, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसको लागू करने को लेकर कई स्तरों पर कोशिश करनी होगी।

एमएनआरई मंत्रालय के अधिकारी मानते हैं कि अभी देश में जितनी बिजली का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में हो रहा है और वर्ष 2030 तक जितनी अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जानी है, उसे देखते हुए चार-पांच वर्षों बाद सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को बिजली देना संभव हो पाएगा। मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्रों की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से बिजली जाए, इसके लिए कई तरह के बदलाव करने होंगे। मौजूदा बिजली वितरण व्यवस्था में भी बड़े बदलाव करने होंगे। बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों में सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, पनबिजली आदि) से बिजली पहुंचाना तो आसान है लेकिन देश के कई हिस्सों में जो मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां स्थित हैं, उन तक इसे कैसे पहुंचाया जाएगा, इसकी व्यवस्था करनी होगी।

4.70 लाख मेगावाट है देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता

भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता अभी 4.70 लाख मेगावाट है, जिसमें 2.14 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी है, जबकि 2.48 लाख मेगावाट के करीब ताप बिजली संयंत्रों का हिस्सा है। इस तरह से कुल बिजली की स्थापित क्षमता में ताप बिजली संयंत्र की हिस्सेदारी 56 प्रतिशत है, लेकिन जब कुल बिजली आपूर्ति की बात होती है तो इनकी हिस्सेदारी अभी भी 72-74 प्रतिशत है।

कुल बिजली खपत में औद्योगिक सेक्टर की हिस्सेदारी 42%

देश में जितनी बिजली की खपत होती है उसमें 42 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक सेक्टर का होता है। घरेलू क्षेत्र में बिजली की खपत कुल खपत का 26 प्रतिशत है, कृषि क्षेत्र में 17 प्रतिशत और वाणिज्यिक सेक्टर में आठ प्रतिशत है। अप्रैल, 2025 में देश में बिजली की कुल खपत (पीक आपर डिमांड) 2.35 लाख मेगावाट पहुंच चुकी है। अगर गर्मी बढ़ी तो यह मांग 2.50-2.60 लाख मेगावाट पहुंच सकती है। इस हिसाब औद्योगिक सेक्टर को अभी के हिसाब से तकरीबन एक लाख से 1.10 लाख मेगावाट बिजली चाहिए।